

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलिय न्यायपालिका

विशेष छूट याचिका (सीआरएल.) सं. 3662 ऑफ 2023

सुप्रिया जैन

.....अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

निर्णय

दीपांकर दत्ता, जे।

छूट प्रदान की गई।

2. दूसरे प्रतिवादी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, थानेसर शहर पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. संख्या 658 दिनांकित 2 अगस्त, 2020 को 7 (सात) अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 406, 420, 506 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था।

3. एफ. आई. आर. की जांच का समापन दंड प्रक्रिया संहिता ("सीआरपीसी", इसके बाद) की धारा 173 (2) के संदर्भ में 14 फरवरी, 2022 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420, 406, 506, 379, 120 बी और 180 के तहत, अन्य बातों के साथ, एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ हुआ।

4. हालाँकि, आरोप-पत्र के अवलोकन से आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत अपराध के संबंध में याचिकाकर्ता की किसी भी भूमिका का पता नहीं चलता है, जिसे 4 अगस्त, 2020 तक दूसरे प्रतिवादी की शिकायत पर एफ. आई. आर. में जोड़ा गया था।

5. इसे संक्षेप में रखने के लिए, एफ. आई. आर. दूसरे प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजी है कि उसे मुख्य आरोपी (जो याचिकाकर्ता की बहन होती है) द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में लगी एक दवा कंपनी की स्थापना के उद्देश्य से कुल 45 लाख रुपये (आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से आर. टी. जी. एस. द्वारा भुगतान) लेकर अलग होने के लिए लुभाया गया था। मुख्य रूप से, मुख्य अभियुक्त, उसके पति और कई अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ दूसरे प्रतिवादी द्वारा उस पर धोखाधड़ी और

बेईमानी के आरोप लगाए गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता सहित सभी अभियुक्तों ने आपराधिक साजिश को अंजाम देने के उद्देश्य से दूसरे प्रतिवादी को आश्वासन दिया था कि प्रमुख अभियुक्त एक बहुत मेहनती और व्यवसाय की समझ रखने वाली महिला थी। जहाँ तक याचिकाकर्ता की भूमिका का संबंध है, दूसरी प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता को मुख्य आरोपी द्वारा उससे मिलवाया गया था और वह उस गिरोह की सदस्य है जिसने उसे धोखा दिया और बेईमानी करी। उपरोक्त के अलावा, प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं है; अन्यथा, यह मुख्य आरोपी, उसके पति और अन्य सह-अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों से भरा हुआ है।

6. हमने देखा है कि आपराधिक अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली आरोप-पत्र में दूसरे प्रतिवादी को धोखा देने या बेईमानी करने में याचिकाकर्ता की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन उसे एक साजिशकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है। आरोप-पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अग्रिम जमानत प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता 30 जुलाई, 2021 को जांच में शामिल हुई थी और निश्चित रूप से उसने एक इकबालिया बयान दिया था, जिस पर अंततः उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था; इसलिए, उस पर आईपीसी की धारा 180 के तहत दंडनीय अपराध करने का भी आरोप लगाया गया था।

7. आरोप पत्र प्राप्त होने पर, आपराधिक अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया और उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र ("सीजेएम", इसके बाद) द्वारा 18 जुलाई, 2022 के एक आदेश द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए गए। इस तरह के आदेश को याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सीआरपीसी के तहत चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र ("एएसजे", इसके बाद) ने 27 सितंबर, 2022 के एक आदेश द्वारा संशोधन को योग्यता की कमी के रूप में खारिज कर दिया।

8. इस स्तर पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का याचिकाकर्ता द्वारा 14 फरवरी, 2022 के आरोप पत्र, 18 जुलाई, 2022 के सीजेएम के आरोप तय करने के आदेश और 27 सितंबर, 2022 के एएसजे के पुनरीक्षण आदेश को चुनौती देने के लिए आह्वान किया गया था। उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की रूपरेखा को रेखांकित करने वाले विभिन्न न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख किया, जब उन्हें एक प्राथमिकी/शिकायत और/या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संपर्क किया जाता है। इस तरह के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए और इस राय के निर्माण के आधार पर

कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई गई थी, उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले और 11 नवंबर, 2022 के आदेश द्वारा चुनौती को खारिज कर दिया और हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया गया।

9. इससे व्यथित होकर, असफल याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष हमारे समक्ष अपील कर रहा है।

10. हमने पक्षों को सुना है और साथ ही आरोप पत्र और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री का अवलोकन किया है।

11. आरोप-पत्र एफ. आई. आर. की सामग्री को निर्धारित करता है और उन सामग्रियों को संदर्भित करता है जो जांच के दौरान एकत्र की गई थीं। जांच अधिकारी ने दूसरे प्रतिवादी और याचिकाकर्ता के सेल फोन का कॉल विवरण रिकॉर्ड (सी. डी. आर.) और ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र (सी. ए. एफ.) प्राप्त किया और संबंधित सेवा प्रदाताओं से संपर्क करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने का भी प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रयास में विफल रहे। उन्हें बताया गया कि बातचीत काफी पुरानी थी, इसलिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका। आरोप-पत्र में यह भी दर्ज किया गया कि प्रमुख आरोपी और सह-आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद, अलग-अलग पूरक चालान तैयार किया जाएगा और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा; फिर भी, याचिकाकर्ता के खिलाफ चालान तैयार करने के लिए फाइल पर पर्याप्त सबूत उपलब्ध थे।

12. इस अपील की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी और उसे अनुमति दी गई। इसके तुरंत बाद, प्रथम प्रतिवादी/राज्य ने 24 अप्रैल, 2023 को एक उत्तर शपथ पत्र दाखिल किया।

13. अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए आवेदन में कई दस्तावेज होते हैं। पहला तात्पर्य 23 जून, 2020 को दो गवाहों की उपस्थिति में प्रमुख अभियुक्त और दूसरे प्रतिवादी द्वारा और उनके बीच किए गए समझौते की अनुवादित प्रति होना है, जिसमें प्रमुख अभियुक्त ने पूरी राशि (₹ 45 लाख) दूसरे प्रतिवादी से प्राप्त किया और यह भी वादा किया कि अगर किसी भी कारण से प्रस्तावित कंपनी स्थापित करने का काम पूरा नहीं हुआ तो दूसरे प्रतिवादी को पूरी राशि 4 बार वापस कर दी जाएगी। दूसरा दस्तावेज कथित तौर पर सम तिथि (23 जून, 2020) का एक बयान है जो मुख्य आरोपी द्वारा 47 लाख रुपये का भुगतान करने का वचन दिया गया

है, जो उसने दूसरे प्रतिवादी से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्राप्त किया था, उस तारीख से एक साल के भीतर उसे दे दिया। तीसरा दस्तावेज़ प्रमुख अभियुक्त के उस बयान का सही अनुवाद होने का भी दावा करता है जिसमें उसने स्वीकार किया था कि एक आयुर्वेदिक कारखाने को बढ़ावा देने और स्थापित करने के लिए दूसरे प्रतिवादी के साथ चर्चा हुई थी, जिसके लिए पक्षकार कई बार मिले थे और मुख्य अभियुक्त को उतनी राशि मिली थी जितनी उसमें दर्शाई गई थी।

14. ये सभी दस्तावेज़ जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहती है, यदि वास्तविक हैं, तो मुकदमे में उसके बचाव के लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे यह तय करने के चरण में सामग्री नहीं हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा अनुरोध किए जाने के अनुसार रद्द करना आवश्यक था या नहीं। इसलिए, हम इन तीन दस्तावेज़ों पर कोई भरोसा करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

15. चौथा दस्तावेज़ जो याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के दावे के समर्थन में रिकॉर्ड पर लाया गया है, वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 सीआरपीसी के तहत दूसरे प्रतिवादी का बयान है, इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, दूसरे प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया था कि उसके द्वारा एक विशेष घर (हाउस नं. 620 सेक्टर-4, कुरुक्षेत्र में) में मुख्य आरोपी को नकद में 9.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, जहां प्रमुख आरोपी, याचिकाकर्ता और उनकी मां मौजूद थे और नकद में इतनी राशि प्राप्त होने पर, "वे" (जिसका अर्थ है कि प्रमुख आरोपी, याचिकाकर्ता और उनकी मां)... ने "पैसे की गिनती की" जो अंततः मुख्य आरोपी के पास रखे गए थे। दूसरे प्रतिवादी ने कहा कि यह उसकी साली इंदु की उपस्थिति में हुआ। इस तरह के बयान में दूसरे प्रतिवादी द्वारा यह भी कहा गया था कि मुख्य आरोपी, उसके पति, याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्तों ने मिलकर उसे उसमें वर्णित तरीके से 45 लाख रुपये की राशि का धोखा दिया है।

16. आरोप-पत्र में 27 (सत्ताईस) गवाहों की सूची है, जिनसे याचिकाकर्ता सहित कई अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ करने का प्रस्ताव है। दूसरे प्रतिवादी और अन्य लोगों के अलावा, इस विशेष सूची में दूसरे प्रतिवादी की साली इंदु शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मकान नं. 620 में मौजूद थी, जब कथित तौर पर पैसे बदले गये।

17. यह एक ऐसा मामला है जिसमें आरोप तय किए गए हैं और आरोपी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऊपर देखे गए तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि जांच

और अनुवर्ती कदम इतने स्पष्ट रूप से और निर्बाध रूप से दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण नहीं हैं (सिवाय उस सीमा के जिसका हम अपना निर्णय समाप्त करने से पहले उल्लेख करने का प्रस्ताव करते हैं) कि मुकदमे को आगे बढ़ने देने से न्याय की विफलता हो सकती है। अभिलेखों में गहराई से जाने के लिए भी यह एक उपयुक्त चरण नहीं है। यह पता लगाना किसी भी अदालत के काम का हिस्सा नहीं है कि मुकदमे का परिणाम क्या हो सकता है, अभियुक्त को दोषी ठहराना या बरी करना। न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से कानून जो छोटी सी गुंजाइश प्रदान करता है, वह है प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को देखना, अभियुक्त द्वारा इसका खंडन किए बिना, और इस पर एक राय बनाना। जब तक अभियोजन पक्ष को अवैध नहीं दिखाया जाता है ताकि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो, तब तक इसे रोकना उचित नहीं होगा। सीआरपीसी की धारा 397 या धारा 482 सीआरपीसी या एक साथ, जैसा भी मामला हो, के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी आरोप/कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांत ने कई बार इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। प्रत्येक मिसाल का संदर्भ अनावश्यक है। हालाँकि, हम लाभप्रद रूप से इस न्यायालय के केवल एक ही निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ इस बिंदु पर लगभग सभी उदाहरणों के सर्वेक्षण पर, इस न्यायालय द्वारा सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र¹ में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए:

"27.1 यद्यपि संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितनी अधिक शक्ति होगी, इन शक्तियों को लागू करने में उतनी ही अधिक देखभाल और सावधानी बरतनी होगी। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति, विशेष रूप से, संहिता की धारा 228 के संदर्भ में बनाए गए आरोप का उपयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में।

27.2. न्यायालय को इस परीक्षण को लागू करना चाहिए कि क्या मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से लगाए गए अनियंत्रित आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं या नहीं। यदि आरोप इतने स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जहां आपराधिक अपराध के मूल तत्व संतुष्ट नहीं हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

27.3. उच्च न्यायालय को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह विचार करने के लिए कि क्या मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा या आरोप तय करने या आरोप को रद्द करने के चरण में नहीं, साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं है।

27.4. जहां इस तरह की शक्ति का प्रयोग न्याय के पेटेंट गर्भपात को रोकने के लिए और कुछ गंभीर त्रुटि को सुधारने के लिए बिल्कुल आवश्यक है जो ऐसे मामलों में भी अधीनस्थ अदालतों द्वारा की जा सकती है, उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन को रोकने के लिए, सीमा पर, हस्तक्षेप करने से घृणा होनी चाहिए।

27.5. जहां संहिता के किसी भी प्रावधान या किसी विशिष्ट कानून में अधिनियमित एक स्पष्ट कानूनी बाधा है जो ऐसी आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत या संस्था और निरंतरता के लिए लागू है, ऐसे प्रतिबंध का उद्देश्य एक आरोपी को विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करना है।

27.6. न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष के अपराधी की जांच और मुकदमा चलाने के अधिकार को संतुलित करे।

27.7. न्यायालय की प्रक्रिया को तिरछे या अंतिम/गुप्त उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

27.8. जहां लगाए गए आरोप और जैसा कि वे अभिलेख और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से मुख्य रूप से सामने आते हैं और 'आपराधिकता के तत्व' के बिना एक 'नागरिक गलत' का गठन करते हैं और एक आपराधिक अपराध के मूल अवयवों को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो अदालत आरोप को रद्द करने में उचित हो सकती है। ऐसे मामलों में भी, अदालत साक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण शुरू नहीं करेगी।

27.9. अदालतों को एक और बहुत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी कि वे यह निर्धारित करने के लिए अभिलेख पर तथ्यों, साक्ष्यों और सामग्रियों की जांच नहीं कर सकते हैं कि क्या पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा; अदालत मुख्य रूप से उन आरोपों से संबंधित है जो समग्र रूप से लिए गए हैं कि क्या वे एक अपराध होंगे और यदि ऐसा है, तो क्या यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो अन्याय की ओर ले जाता है।

27.10. यह न तो आवश्यक है और न ही अदालत से पूर्ण जांच करने या जांच एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की सराहना करने के लिए कहा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह बरी होने या दोषसिद्धि का मामला है।

27.11. जहां आरोप एक दीवानी दावे को जन्म देते हैं और एक अपराध के बराबर भी होते हैं, केवल इसलिए कि एक दीवानी दावा बनाए रखने योग्य है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक आपराधिक शिकायत को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

27.12. धारा 228 और/या धारा 482 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय किसी अभियुक्त द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दी गई बाहरी सामग्री पर विचार नहीं कर सकता है कि किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया था या उसके बरी होने की संभावना थी। न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा संलग्न अभिलेख और दस्तावेजों पर विचार करना होगा।

27.13. आरोप को रद्द करना निरंतर अभियोजन के नियम का एक अपवाद है। जहाँ अपराध व्यापक रूप से भी संतुष्ट है, वहाँ न्यायालय को उस प्रारंभिक चरण में इसे रद्द करने के बजाय अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए। अदालत से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह दस्तावेजों या अभिलेखों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता तय करने की दृष्टि से अभिलेखों का संचालन करे, लेकिन यह एक राय है जो प्रथम दृष्टया बनाई गई है।

27.14. जहां संहिता की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र, रिपोर्ट, मौलिक कानूनी दोषों से ग्रस्त है, वहां न्यायालय आरोप तय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में हो सकता है।

27.15. उपरोक्त में से किसी भी या सभी के साथ, जहां न्यायालय को लगता है कि यह संहिता की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय का हित अनुकूल होगा, अन्यथा वह आरोप को रद्द कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग एक्स डेविटो जस्टिटिया अर्थात् प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए जिसमें केवल अदालतें मौजूद हैं।

* * *

27.16. ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से और अधिमानतः संचयी रूप से (एक या अधिक) उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 482 के तहत असाधारण और व्यापक पूर्णता और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए उपदेशों के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहाँ अपराध के लिए तथ्यात्मक आधार निर्धारित किया गया है, वहाँ अदालतों को अनिच्छुक होना चाहिए और इस आधार पर भी कार्यवाही को रद्द करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक या दो तत्व नहीं बताए गए हैं या अपराध की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन होने पर संतुष्ट नहीं प्रतीत होते हैं।"

18. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यापक सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक नहीं है जहां अभिलेख पर सामग्री से प्रकट होने वाले अनियंत्रित आरोपों के बावजूद, यह सफलतापूर्वक तर्क दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी अपराध को करने की ओर इशारा करते हुए कोई प्रथम दृष्टया राय भी नहीं बनाई जा सकती है। यह सामान्य बात है कि अपराध करने की साजिश अपने आप में उस अपराध से अलग है जिसमें साजिश की गई है और ऐसा अपराध, यदि वास्तव में किया गया है, तो एक अलग आरोप का विषय होगा। यह आरोप कि याचिकाकर्ता को एक सूचीबद्ध गवाह की उपस्थिति में दूसरे प्रतिवादी से मुख्य आरोपी द्वारा प्राप्त नकदी को गिनते

हुए पाया गया था और कि उसने अपनी बहन, प्रमुख आरोपी के साथ मिलकर दूसरे प्रतिवादी को धोखा देने और धोखा देने की साजिश रची, हमें यह दर्ज करने के लिए राजी करता है कि याचिकाकर्ता की भागीदारी, चाहे कितनी भी सीमित हो, इस स्तर पर खारिज नहीं की जा सकती है और इसलिए, मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए और वह मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य है।

19. उपरोक्त कारणों से, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को बरकरार रखते हैं। पीसी। निचली अदालत किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकती है।

20. अलग होने से पहले, हम एक ऐसे पहलू का विज्ञापन करना आवश्यक समझते हैं जिसका पक्षकारों द्वारा हमारे लिए उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन पहले प्रतिवादी/राज्य के उत्तर शपथ पत्र से देखा गया है।

21. इस तरह के उत्तर शपथ पत्र का प्रतिनिधि पुलिस उपाधीक्षक ("डीएसपी", इसके बाद) का पद धारण करता है। उन्होंने इसके पैराग्राफ 5 में साहसपूर्वक इस प्रकार कहा है:

"अदालत ने आगे कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने अपना स्वीकारोक्ति बयान 30.07.2021 दिनांकित दर्ज किया जिसमें उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ शिकायतकर्ता से मिली थी और शिकायतकर्ता से उसे 9 लाख रुपये की राशि मिली थी, जिसे बाद में उसकी बहन और सह-आरोपी प्रियंका मित्तल को सौंप दिया गया। उसने आगे स्वीकार किया कि उसे अपने हिस्से के रूप में 2 लाख रुपये की राशि मिली, जो उन्होंने व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च किए थे। यह उल्लेख करना उचित है कि उसका दिनांकित 30.07.2021 बयान दर्ज कराने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपने बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उसे आईपीसी की धारा 180 के तहत अपराध करने के लिए भी आरोप पत्र दायर किया गया था।"

22. हम यह जानकर हैरान हैं कि डीएसपी रैंक का एक अधिकारी इस अदालत के समक्ष दायर किए जाने वाले शपथ पत्र की शपथ लेते समय इतना गैर-जिम्मेदार हो सकता है। एक अधिकारी, जो एक डीएसपी है, को यह पता होना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के संदर्भ में, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय बारह के तहत किसी भी जांच के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई बयान नहीं, जिसे लिखने तक सीमित कर दिया गया है, को बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है और आई. पी. सी. की धारा 180 केवल तभी आकर्षित होती है जब एक बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जाता है, जो एक लोक सेवक कानूनी रूप से बयान देने वाले व्यक्ति

से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता के लिए सक्षम है। यहाँ ऐसा मामला नहीं है। चूंकि साक्षी को हमारे द्वारा नहीं सुना गया है, इसलिए हम इस मुद्दे को आगे ले जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, बल्कि उसे भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं।

23. सी. जे. एम. के 18 जुलाई, 2022 के आदेश से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 180 के तहत कोई आरोप तय किया गया है; हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अलग आदेश द्वारा कोई आरोप तय किया गया है, तो वह कानून के अनुसार अपना उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

24. ऊपर उल्लिखित सीमा को छोड़कर, अपील बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

25. इस निर्णय की एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उत्तर शपथ पत्र के प्रतिवादी के हित के प्रतिकूल कोई कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भेजी जाएगी कि सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाए और कानूनी प्रावधानों की अज्ञानता से लंबित आपराधिक कार्यवाही पर आरोपी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

..... जे.

(एस. रवींद्र भट्ट)

..... जे.

(दीपांकर दत्ता)

नई दिल्ली;

जुलाई 04, 2023

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।